>

Title: Need to fix the minimum support price of potato.

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): देश में आलू माटी के मोल बिक रहा है। किसान बेहाल है और त्राहि-त्राहि कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में सहयोगी विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में संलग्न लोगों का तकरीबन 65 फीसदी कृषि कार्यों में लगा है। किसानों के मेहनत-पसीने से इस वर्ष पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। बंपर उपज से किसानों को बंपर कमाइ होनी चाहिए थी परंतु इसका उल्टा हो रहा है। आज आलू किसान दर-दर अपने आलू को बेचने के लिए भटक रहा है, उसकी उपज को खरीदने वाला कोई नहीं है और यदि बिक भी रहा है तो वह उत्पादन लागत भी नहीं दे रहा है।

आलू की उत्पादन लागत 3.5 रूपये प्रति किलो के करीब पड़ती है जबकि उत्पादन लागत से कम मूल्य पर किसानों द्वारा तकरीबन 2 से 3 रूपये प्रति किलो आलू थोक मंडियों में बेचना पड़ रहा है। बंपर उत्पादन से राज्यों के सभी कोल्डस्टोरेज मुंह मांगी रकम आलू को स्टोर करने में वसूल रहे हैं और हाउसफुल हैं। ऐसे में किसान हतोत्साहित हैं और वह आलू को खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ रहा है।

अत्यंत दुख की बात हे कि सरकार द्वारा इस बंपर पैदावार की जानकारी के बाद भी आलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। मेरी मांग है कि सरकार आलू किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करें और नेफेड जैसी सरकारी एजेंसियों की सेवाएं लेकर उचित मूल्य पर आलू की खरीददारी करें ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके एवं आलू की फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके।